IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 13 | सांचौर, सोमवार, 1, जुलाई 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारम्भ

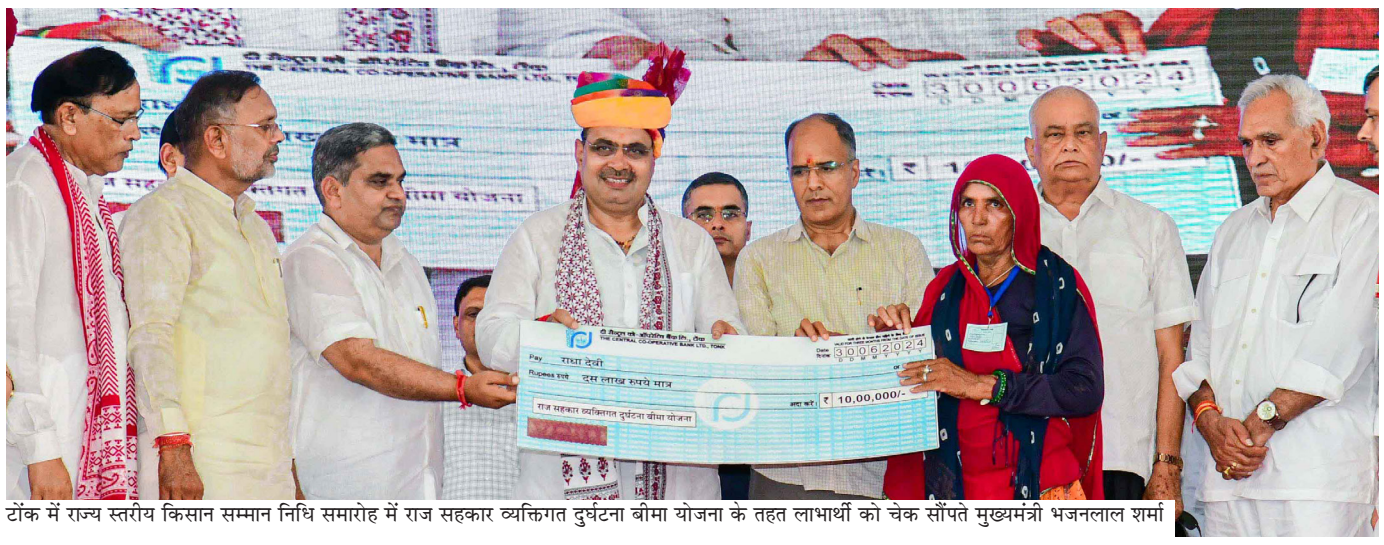

टोंक में राज्य स्तरीय किसान सम्मान निधि समारोह में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थी को चेक सौंपते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

प्रधानमंत्री ने दिया देश के किसानों को सम्मान एवं संबल प्रदेश के अन्नदाता को बनाएंगे समृद्ध - शर्मा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के लिए अन्न उपजाने वाले किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाना हमारी डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार की ओर से किसान कल्याण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान की समृद्धि से ही विकसित और खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होगा।

हमारी सरकार संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री रविवार को टोंक की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के राज्यस्तरीय शुभारम्भ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 हजार रुपए की राशि के साथ ही, 2 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसी क्रम में आज राज्य सरकार की ओर से एक हजार रुपए की पहली किस्त के तौर पर 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपए सीधे जमा किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में गेहूं के 2275 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपए का बोनस प्रदान कर 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद की गई है। प्रदेश में 10 हजार सौर ऊर्जा संयंत्रों, 41 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर तथा 44 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना की गई है। राज्य के 47 हजार किसानों को कृषि कनेक शन जारी किए गए हैं। किसानों को बिजली के बिलों में 8 हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है।

किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने तथा प्रदेश को बिजली सरप्लस राज्य बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं। प्रदेश के 80 हजार से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण मिला है तथा 21 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याजमुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 100 नई पैक्स का गठन किया गया है। पशुपालकों के लिए त्वरित पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल वेटेनरी सेवा प्रारंभ की गई है। वहीं राज्य के 20 हजार किसानों को फार्म पौंड की सौगात दी गई है।

65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपये हस्तांतरित

21 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की होगी स्थापना

80 हजार किसानों को मिला 350 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण

20000 किसानों को मिली फार्म पौंड की सौगात

केन्द्रीय योजनाओं से प्रदेश के किसान हो रहे हैं लाभान्वित

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 1 हजार 400 करोड़ रुपए बीमा क्लेम का वितरण किया गया, 9 हजार पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर सो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना चलाई जा रही है

अपेक्स बैंक प्रबंध निदेशक धनसिंह देवल भीनमाल पहुंचने पर बैंक एवं पैक्स कर्मियों ने किया स्वागत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक धनसिंह देवल के जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा भीनमाल प्रवास के दौरान शाखा प्रबंधक नंद किशोर सोनी एवं शाखा कार्यक्षेत्र में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने प्रबंध निदेशक का स्वागत कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपकर, सहकारी समिति कर्मियों का कैडर गठन करने और सहकारी समिति स्तर पर एफआईजी के माध्यम से पास बुक प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ खरीफ ऋण वितरण में बढ़ोतरी करने सहित सहकारी समितियों को फसल बीमा कमीशन एवं राज्य सरकार और भारत सरकार से देय 3 प्रतिशत व 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान समय पर उपलब्ध करवाने की मांग रखने पर, शीर्ष बैंक प्रबंध निदेशक श्री धनसिंह देवल द्वारा शीघ्र सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया गया, साथ ही, श्री देवल ने उपस्थिती व्यवस्थापकों को ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक कार्य कर किसानों की सेवा करने और विविध गतिविधियों यथा जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, कस्टम हायरिंग सेंटर आदि का संचालन समितियों के माध्यम से कर समितियों की लाभदायकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया । इस दौरान बैकिंग सहायक विवेक उपाध्याय सहित समिति व्यवस्थापक गोविंद सिंह कावतरा, ईश्वर लाल जुंजानी, मोहनलाल वाड़ा भाड़वी, जगदीश चौधरी जोगाऊ, बाबूलाल सेन मिंडावास, दुदाराम बोरटा, हरीश भागलसेफ्टा आदि मौजूद थे।

खुशी और गौरव का विषय - सेन

राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ब्लॉक इकाई भीनमाल के ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सेन ने कहा कि सहकारिता सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धनसिंह जी देवल पूर्व समय में जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थ रहे थे, अब उनका प्रदेश की शीर्ष सहकारी बैंक यानि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक पद का दायित्व मिलना, हम सबके लिए खुशी और गौरव का विषय है ।

पात्र जन को मिले सरकार की योजनाओं का लाभ

जयपुर। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री व सवाईमाधोपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लालशर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जीरों टोलरेंस पर कार्य कर रही है किसी भी प्रकार की लापरवाही सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना को निर्देशित किया कि मानसून को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं का भण्डारण व इसकी आपूर्ति नियमित रूप से सीएचसी, पीएचसी पर करवाई जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव करवाया जाना सुनिश्चित करें व एमपैनल्ड निजी अस्पतालों में राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

काछौली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड काछौली

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

श्री शैतानसिंह
अध्यक्ष

श्री खीमसिंह
उपाध्यक्ष

श्री मनीष कुमार
सहायक व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

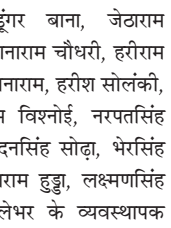

श्री सुरेन्द्रसिंह देवड़ा
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : ■ अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरण ■ कृषि जिंस भंडारण ■ समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद ■ कृषि यंत्रीकरण ■ कृषि आदान ■ पीडीएस

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

वार्ता के पश्चात धरना समाप्त

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के आगे भीषण गर्मी में सहकारी समितियां व्यवस्थापक यूनियन यूनिट बाड़मेर के बैनर तले चल रहा अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया हैं, यूनियन महासचिव भंवराराम चौधरी ने बताया कि दी बाड़मेर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई एवं अधिशासी अधिकारी हरीराम पूनिया के साथ यूनियन जिला अध्यक्ष रायमलराम नेहरा की मौजूदगी में हुई वार्ता के पश्चात 18 जून को ज्ञापन के जरिए रखी गई छह सूत्री मांगों में से एक को छोड़कर बाकि पर सहमति बनने पर धरना समाप्त कर दिया गया,

वही, यूनियन की पूर्व की भांति ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 15 लाख रुपए की राशि अग्रीम दिए जाने की मांग को लेकर प्रबंध निदेशक ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर निस्तारित करवाने का आश्वासन दिया । इस दौरान समिति व्यवस्थापक हेमसिंह राठौड़, डूंगर बाना, जेठाराम भादू, हनुमानाराम चौधरी, हरीराम चौधरी, कानाराम, हरीश सोलंकी, भागीरथराम विश्नोई, नरपतसिंह गोदारा, मदनसिंह सोढ़ा, भेरसिंह बेरड़, चैनाराम हुड्डा, लक्ष्मणसिंह सहित जिलेभर के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक उपस्थित थे,

दोषी कार्मिकों और पदाधिकारियों के खिलाफ सूरतगढ़ सदर थाने में परिवाद दर्ज

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

श्रीगंगानगर,। जानकीदासवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्मिकों और पदाधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं गड़बड़ी

करने के प्रकरण में जांच के पश्चात सूरतगढ़ सदर थाने में परिवाद दर्ज करवाया गया है। दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक श्री संजय गर्ग ने बताया कि जानकीदासवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के विरूद्ध 11 जून 2024 को जांच परिणाम के पश्चात व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक सहित अन्य पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकरणों में वित्तीय, प्रशासनिक एवं आपराधिक उतरदायित्व के लिये दोषी पाया गया। जांच परिणाम अनुसार कुल वित्तीय उतरदायित्व 14067970.10 रूपये की वसूली के लिये उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा वसूली कार्यवाही आरम्भ की गई है और दोषी कार्मिकों और पदाधिकारियों के खिलाफ 20 जून 2024 को सूरतगढ़ सदर थाने में परिवाद दर्ज करवाया गया है। सहायक व्यवस्थापक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है और विशेष लेखा परीक्षक को गत वर्षों में लेखा परीक्षक रहे अंकेक्षकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिये लिखा गया है।

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र 3 जुलाई से

जयपुर,। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा का द्वितीय सत्र बुधवार 3 जुलाई से आरंभ होगा। विधान सभा सचिवालय ने सत्र के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंध कर लिया है। सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सत्र से संबंधित की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। विधान सभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने चर्चा की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट विधान सभा को प्रस्तुत की जा रही है।

कृषि विभाग द्वारा जनजातिय क्षेत्र में मक्का का निःशुल्क वितरण किया गया

सिरोही,। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे है। कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2024 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के जनजाति उप योजना क्षेत्र के जनजाति श्रेणी के समस्त कृषकों को मक्का संकर बीज मिनी किट नि:शुल्क वितरण कृषि विभाग द्वारा जनजातिय क्षेत्रों में किया जा रहा है। बीज की आपूर्ति राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा की गई है। संकर मक्का की उन्नत किस्म का बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में लगभग 20 केंद्रो से कृषकों को 5 किलो साइज का मक्का मिनी किट उनके जन आधार कार्ड के नंबर को विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर ओटीपी प्राप्त कर दिया जा रहा है। एक पात्र कृषक परिवार को 1 मिनी किट उपलब्ध कराया जा रहा है।

पुराने ऋण चुकाकर ले सकेंगे नया ऋण

अजमेर,। शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना अन्तर्गत कृषक अपना पुराना ऋण चुकाकर नया ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अजमेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री भंवर सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण फ्लेगशीप योजनान्तर्गत कॉ-ऑपरेटिव बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर ऋण चुकारा करने वाले किसानों को ब्याज नहीं देना होता। चुकारा नहीं करने से देय तिथि के पश्चात् किसान को 10 प्रतिशत ब्याज देना होता है। खरीफ 2023 (एक अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक) अंतर्गत वितरित ऋण चुकाने की देय तिथि राज्य सरकार द्वारा ऋण वितरण तिथि से अग्रिम एक वर्ष अथवा 30 जून 2024 जो भी पहले हो निर्धारित की गई है।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

90 समितियों पर भी कर्ज | समितियों द्वारा ऋण न चुका पाने के कारण बढ़ सकती हैं किसानों की समस्या

एक लाख किसानों पर है 342 करोड़ रुपए का फसली ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बांसवाड़ा ; जिले में संचालित 237 वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लैपस) में 90 समितियां दी बांसवाड़ा सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के 2.88 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबी हैं। इनमें 22 समितियां ऐसी हैं, जिन्होंने समय सीमा बीत जाने के बाद भी बैंक का 75.15 लाख रुपए नहीं चुका है। खाद के लिए गए इस अल्पकालीन ऋण के समितियों के द्वारा न चुका पाने के कारण अब किसानों को दिक्कत उठानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं जिले के तकरीबन एक लाख एक हजार 80 किसान पर 342.10 करोड़ रुपए कर्ज के तले दबे हैं।जिले के किसानों के द्वारा बैंक से लिया गया फसली अल्पकालीन ऋण 342.10 करोड़ रुपए की 40.70 प्रतिशत रकम यानी 139.26 करोड़ रुपए किसान अभी तक नहीं चुका पाए हैं। जबकि ऋण चुकाने की अवधि भी पार हो चुकी है। वहीं, समय सीमा के भीतर किसानों पर अभी 202.84 करोड़ रुपए की बकाया है। फसली अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों में 13 हजार किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऑफलाइन और 88,080 किसानों ने ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

किसानों को यों आ सकती है दिक्कत

समितियों के द्वारा लोन न चुकाए जाने से किसानों के आगे दिक्कत खड़ी हो सकती है क्योंकि किसानों को कम कीमत पर खाद, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए वस्तुओं की खरीदी करनी पड़ती है। लेकिन लोन न चुकाए जाने की स्थिति में समिति किसानों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदी नहीं कर पाती। इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता है।

समितियों पर पड़ती है दोहरी मार

किसान के द्वारा समिति के माध्यम से लिया गया अल्पकालीन फसली ऋण हो या कृषि उपयोगी वस्तुओं की खरीदी के लिए समिति के द्वारा लिया गया ऋण हो, बैंक को न चुकाने की मार समिति पर ही पड़ती है। फिर चाहें किसान न चुकाए या समिति देने में अक्षम हो। दोनों ही सूरतों में बैंक समिति को ऋण नहीं देती है। बकाया चुकाने के बाद ही बैंक ऋण जारी करती है।

-वीरेंद्र भट्ट, अध्यक्ष, ठीकरिया लैम्पस उए

फैक्ट फाइल

35,800 रुपए औसतन पुराने किसानों को लोन देती हैं बैंक

15000 रुपए लोन मिलता हैं बैंक से नए जुड़ने वाले किसानों को

237 समितियां संचालित हैं जिले में

बैंक समितियों को देती है नोटिस

समितियों के द्वारा ऋण न चुकाए जाने की स्थिती में समितियों को पत्र भेज ऋण चुकाने के लिए निर्देशित किया जाता है। समय अधिक बीतने पर बैंक नोटिस जारी करता है।

परेश पंड्या, प्रबंधक, सीसीबी, बांसवाड़ा

1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे तीन नए आपराधिक कानून

नई दिल्ली । तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम कल से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

जोगापुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जोगापुरा

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

मोहब्बतसिंह
अध्यक्ष

भरत कुमार मीणा
व्यवस्थापक

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

खेती-किसानी के लिए बने समग्र समावेश नीति

राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कृषि-खाद्य नीति की बहुत चर्चा होती रही है। इसके बावजूद ऐसी समग्र नीति नहीं बन पाई है, जिसमें सभी जरूरतों का संतुलित समावेश हो सके। ऐसी समग्र नीति में आठ उद्देश्यों का संतुलित निर्वाह होना चाहिए, जो परस्पर एक-दूसरे से जुडे हुए हैं पहला उद्देश्य तो यह है कि किसानों को, विशेषकर छोटे और मध्यम किसानों को संतोषजनक, टिकाऊ और रचनात्मक आजीविका उपलब्ध हो। संतोषजनक का मतलब उन्हें उपज की उचित कीमत मिले, जिससे जीवन-निर्वाह के अनुकूल आय प्राप्त हो। टिकाऊ का अर्थ आजीविका व इसका आधार भावी पीढी के लिए भी टिका रहे। पानी-मिट्टी जैसी खेती की बुनियादी जरूरतें अच्छी स्थिति में बनी रहें। रचनात्मक का अर्थ खेती-किसानी के ज्ञान का किसान बेहतर उपयोग कर सकें, जिसमें परंपरागत ज्ञान और महिला किसानों की समझ की बडी भूमिका है। खर्च और कर्ज में कमी जरूरी है। दूसरा उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को ऐसे खाद्य पदार्थ उचित कीमत पर मिलें, जो उन्हें स्वस्थ व नीरोग रखें। तीसरा उद्देश्य यह है कि कृषि और गांव का पर्यावरण अच्छा रहे। भू-जल स्तर ठीक बना रहे, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति बनी रहे, जल-स्रोत उपलब्ध हों, किसान के मित्र, जो कीट-पतंगे, मधुमक्खियां, पक्षी आदि हैं, उनकी भी रक्षा हो तथा परागण की क्रिया ठीक से हो। सभी गांवों में भरपूर स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष रहें। परंपरागत बीजों की रक्षा भी बहुत जरूरी है। चौथा उद्देश्य यह है कि जलवायु बदलाव के मौजूदा दौर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम रखा जाए और इस कारण उत्पन्न प्रतिकूल मौसमी स्थितियों व आपदाओं का सामना करने की क्षमता विकसित हो। बुरे मौसम और आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले से बेहतर तैयारी करनी होगी। यदि ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने का कार्य ठीक से हो, तो इसके लिए विश्व स्तर पर स्थापित कोष से धनराशि प्राप्त की जा सकती है और किसानों को दी जा सकती है। पांचवां उद्देश्य है कि भूमिहीन खेत मजदूरों को बेहतर मजदूरी और जहां संभव हो, कुछ भूमि देकर उनकी सहायता की जाए। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की भलाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा। विशेषकर डेयरी व पशुपालन, किचन गार्डन आदि के माध्यम से भी इनकी मदद हो सकती है। छठा उद्देश्य है कि खेती के उत्पादों पर आधारित लघु और कुटीर उद्योगों को बढावा दिया जाए। क्योंकि, केवल खेती से गांव और गांव के लोगों की समृद्धि का मजबूत आधार नहीं बनता है। इससे स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार का सृजन भी होगा। इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सातवां उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न भागों की अलग-अलग स्थितियों के अनुसार कृषि विकास की अलग-अलग जरूरतों के अनुकूल नियोजन होने चाहिए। यानी विकेंद्रित स्थानीय जरूरतों के अनुकूल कृषि नीति पर अधिक जोर देना चाहिए। आठवां और अंतिम उद्देश्य यह है कि खेती और ग्रामीण विकास के लिए सरकारों को अपना बजट बढाना चाहिए। एक बार किसानों के कर्ज को माफ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि सस्ती तकनीक अपना कर वह आगे कर्ज से बच सकें। बेशक इन सब उद्देश्यों का एक साथ एक समग्र संतुलित नीति में समावेश चुनौतीपूर्ण है। लेकिन, इस राह पर चलते हुए हम बहुत बडी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इन सभी उद्देश्यों में कोई आपसी टकराव नहीं है। इन सभी उद्देश्यों को हम एक साथ एक समय में समावेशी नीति से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें यह ध्यान में रखना पडेगा कि जब तक इन नीतियों के साथ कुछ समाज-सुधार के कार्य नहीं जुडेंगे, तब तक बेहतर से बेहतर आर्थिक नीतियां भी सफल नहीं होंगी। नशे के विरुद्ध, दहेज के विरुद्ध सशक्त आवाज उठानी होगी। तरह-तरह की उपभोक्तावाद आधारित फिजूलखर्ची को भी कम करना ही होगा। आज की दुनिया में शॉर्ट-कट बहुत पसंद किए जाते हैं। ऐसे में, आश्चर्य नहीं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को छोडकर प्रायः सतही तौर पर एक-दो उद्देश्यों या फार्मूलों पर चर्चा होती रही है। लेकिन, सही और टिकाऊ समाधान तभी मिलेंगे, जब इनके लिए समग्र नीतियां बनेंगी, जब अल्पकालीन हितों के साथ दीर्घकालीन हितों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

जीवन के लिए बढ़ता तापमान बन रहा है जानलेवा

-ज्ञानेन्द्र रावत
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अत्याधिक तापमान का असर इंसान के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। असलियत में दुनिया की करीब 81 फीसदी आबादी भीषण गर्मी झेलने को विवश है। अमेरिका भी गर्मी की मार से बेहाल है। उसने माना है कि गर्मी के भीषण हालात से मरने वाले बीते दशक में दोगुने से भी ज्यादा हो गये हैं। यूएसए की संस्था सीडीएस ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है।

एक महीने से भी ज्यादा समय से अधिकतमतापमान 40 डिग्री से ऊपर बना सा हुआ है जबकि राजस्थान के जैसलमेर में इस दौरान पारा 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पारा दिल्ली में पिछले 80 साल का और पंजाब 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस बीच दिल्ली में पारे की सीमा 52.9 तक पार कर चुकी है। अब भी यहां का तापमान 44.9 के आसपास है जो बीते दिन 51 तक पहुंच गया जबकि बिहार 46.9 डिग्री को पार कर चुका है। यही स्थिति कमोबेश देश के सभी उत्तरी राज्यों की है जो चिलचिलाती धूप और भीषण लू के थपेड़ों के चलते त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। गर्मी के चलते दिन में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। लोग गर्मी की वजह से घरों से नहीं निकल रहे हैं। इस कारण सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले ग्राहकों को तरस गये हैं। बाजार में भी ग्राहकों की तादाद में भारी गिरावट आयी है। गर्मी की मार से क्या पहाड़ और क्या मैदानी इलाके कोई भी अछूते नहीं रहे हैं। इस बार गर्मी ने पहाड़ों पर भी रिकार्ड तोड़ दिया है। हिमाचल और उत्तराखंड भी इस गर्मी से अपने को बचा नहीं सके हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज 47.6 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। जम्मू के कठुआ में तापमान 48.5 डिग्री पार कर गया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाके भी गर्मी से बेहाल हैं। हालत इतनी खराब है कि वह चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या फिर चंडीगढ़ दिन तो क्या रात में भी गर्मी की मार से तपते रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग रोज मौत के मुंह में जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार हम वैश्विक गर्मी की यह भयावहता देख रहे हैं जिसकी अब तक विश्व के पर्यावरणविद् और विज्ञानी केवल कल्पना भर ही कर रहे थे। आने वाला समय और भयावह होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले पांच साल में पहली बार वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के 66 फीसदी आसार हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वैश्विक तापमान की सीमा छूने का अर्थ है कि विश्व 19वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से के मुकाबले अब 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। दुनिया में तापमान में हो रही बेतहाशा बढोतरी भयावह खतरे का संकेत है। जलवायु परिवर्तन और अलनीनो ने इसमें अहम भूमिका निबाही है। यह सब कोयला, तेल और गैस के जलाने की सभी सीमाएं पार करने का दुष्परिणाम हैं। फिर बीते सालों की रिकार्ड तोड़ प्राकृतिक घटनाओं को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने में तत्परता से कारगर कदम उठाने में वैश्विक समुदाय उतना सजग नहीं दिखता जितना होना चाहिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की मानें तो न केवल बीता वर्ष बल्कि पूरा बीता दशक धरती पर अभी तक का सबसे गरम दशक रहा है। और 2014 के बाद यह जून का महीना सबसे गर्म रहा है। इस वर्ष की रिकॉर्ड गर्मी की शुरूआत ने 12 माह के औसत तापमान को उस स्तर से आगे बढ़ा कर 1.5 डिग्री को लांघ दिया है। चिंता की बात यह है कि यदि तापमान वृद्धि की दर पर अंकुश नहीं लगा तो सदी के अंत तक गर्मी से 1.5 करोड़ लोग मौत के मुहाने तक पहुंच जाएंगे।

अमेरिका की पर्यावरण संस्था ग्लोबल विटनेस और कोलंबिया यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि तेल और गैस का अत्याधिक मात्रा में उत्सर्जन वह अहम कारण है जिसके चलते उत्सर्जन स्तर यदि 2050 तक यही रहा तो 2100 तक गर्मी अपने घातक स्तर तक पहुंच जायेगी जिसका नतीजा लाखों लोगों की मौत के रूप में सामने आयेगा। बीते वर्षों के अध्ययन से पता चलता है कि अकेले 2022 में 60 हजार से ज्यादा लोगों की मौत गर्मी के चलते हुयी। अत्याधिक तापमान का असर इंसान के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। असलियत में दुनिया की करीब 81 फीसदी आबादी भीषण गर्मी झेलने को विवश है। अमेरिका भी गर्मी की मार से बेहाल है। उसने माना है कि गर्मी के भीषण हालात से मरने वाले बीते दशक में दोगुने से भी ज्यादा हो गये हैं। यूएसए की संस्था सीडीएस ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है।

हालात इतने खराब हो गये हैं कि इंसान तो इंसान, पेड़ पौधे भी बढ़ते तापमान के बीच सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसका अहम कारण पेड़ों में सांस लेने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की क्षमता कम होते जाना है। गर्म और सूखे जलवायु के कारण वायुमंडल से कार्बन डाई आक्साइड के अवशोषण की प्रक्रिया में पेड पौधों का असफल होना है। बोस्टन, कोलंबिया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि इससे भुखमरी, सूखा और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। खासकर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर इसका घातक असर होगा।

हर एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ हृदय रोगियों की मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। किडनी की बीमारी वाले रोगियों के लिए गर्मी जानलेवा हो सकती है। लम्बे समय तक अधिक तापमान में रहने से शरीर का थर्मल सिस्टम फेल हो जाता है। शरीर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाये तो शरीर के मैटाबोलिज्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समस्या की असली जड़ जीवाश्म इंधन है जिससे हमें दूर जाने की बेहद जरूरत है।

किसानों को वितरित हो रहा अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । केन्द्रीय सहकारी बैंक की मण्डार शाखा अंतर्गत संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों की ओर खरीफ सीजन में किसानों को बैंक द्वारा आंवटित लक्ष्य के अनुरुप ऋण

वितरित किया जा रहा हैं, सोरड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा खरीफ सीजन में बैंक की ओर आंवटित किए गए खरीफ ऋण वितरण के लक्ष्य के मुकाबले 90 फिसदी तक 737 किसानों को 4 करोड़ 81 रुपए का फसली सहकारी ऋण वितरित किया गया हैं, इसी प्रकार, शाखा की रायपुर आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से भी आंवटित लक्ष्य के मुकाबले 732 किसानों को 4 करोड़ 68 लाख से ज्यादा का ऋण वितरण एवं मगरीवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से 257 किसानों को 1 करोड़ 50 लाख, जैतावाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा 366 किसानों को 1 करोड़ 86 लाख ऋण वितरण किया हैं, तो वही, हाल ही सालों में गठित हुई बांट सहकारी समिति द्वारा 232 किसानों को 1 करोड 12 लाख रुपए और वरमान ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा 79 किसानों को 41 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया हैं, जबकि शाखा मुख्यालय की मण्डार ग्राम सेवा सहकारी समिति को आंवटित लक्ष्य 2 करोड़ 40 लाख के मुकाबले 2 करोड़ 1 लाख तक का ही ऋण वितरण हुआ हैं, वही समिति में 635 किसानों का पंजीयन होने के बावजुद अब तक 409 किसानों को ही ऋण मुहैया कराया गया है। गौरतलब हैं कि खरीफ सीजन में अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरण का कार्य 31 अगस्त तक चलता हैं, वही, गत रबी सीजन के दौरान वितरित ऋण की वसूली जमा करवाने पर खरीफ सीजन में ऋण मुहैया करवाया जाता हैं। राज्य सरकार की ओर से रबी सीजन के बकाया ऋण की वसूली जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित हैं ।

किसानों को मुहैया कराया जा रहा अल्पकालीन फसली ऋण

जालोर । केन्द्रीय सहकारी बैंक की जसंवतपुरा एव रामसीन शाखा अंतर्गत

चान्दुर समिति स्तर पर ऋण वितरण कार्य करते हुए समिति व्यवस्थापक तलकाराम

संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा समिति कार्यक्षेत्र के ऋणी किसान सदस्यों को खरीफ सीजन में अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण मुहैया कराने के, अलावा गत रबी सीजन के दौरान वितरित ऋण की वसूली का कार्य अनवरत किया जा रहा हैं, साथ ही, अपेक्स बैंक एवं सीसीबी से प्रदत्त निर्देशानुसार किसानों की साख सीमा का नवीनीकरण करने के पश्चात ऋण वितरण किया जा रहा हैं द्य फसली सहकारी ऋण पोर्टल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक चान्दुर ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से 618 किसानों को 2 करोड़ 65 लाख का ऋण वितरित किया गया हैं, इसी तरह जसवंतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा 295 किसानों को 94 लाख, सिकवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से 407 किसानों को 1 करोड़ 51 लाख, सावीदर ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से 508 किसानों को 1 करोड़ 97 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

कैलाशनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

श्री ईश्वरसिंह
अध्यक्ष

श्री प्रवीण कुमार
उपाध्यक्ष

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

श्री ईश्वरसिंह देवड़ा
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : ■ अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरण ■ कृषि जिंस भंडारण ■ समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद ■ कृषि यंत्रीकरण ■ कृषि आदान ■ पीडीएस

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

7 नवीन महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश के चार जिलों में 7 नवीन महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति गठन के लिए, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई हैं, जिसमें भरतपुर जिले गुर्धा नदी, श्रीगंगानगर की 12 एल.एन.पी, जालोर की रानीवाड़ा खुर्द, झाब, खैरथल-तिजारा की चैपानकी, मकडावा, जालावास में नवीन महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन किया जाएगा, इसके लिए स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम 5 वर्ष हेतु भवन उपलब्ध कराया जायेगा तथा गोदाम निर्माण के लिए 1500 वर्गमीटर का भूखंड निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, महिला सहकारी समितियों के सृजन एवं संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक महिला

बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति को हिस्सा राशि के रूप में 3 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई हैं, सहकारिता विभाग के पंजीयक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, समिति का पंजीकरण 15 दिन में करवाना होगा, उसके पश्चात ही हिस्सा राशि समिति को हस्तांतरित की जायेगी। राशि हस्तांतरण के 7 दिन में उपयोगिता प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय को भिजवाना होगा। हिस्सा राशि का उपयोग केवल हिस्सा राशि के रूप में ही किया जा सकेगा।

जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में आर्थिक विकास की मजबूत आधार बनी प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितिया

सहकारिता आंदोलन की सबसे छोटी एवं मजबूत इकाई प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां गांवों में हो रही अच्छा मंच सिद्ध

प्रकाश वैष्णव
Www.marwadkamitra.in

जयुपर । प्रदेश के जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की एक सुदृढ़ परंपरा है। वर्ष 2015 से इसके दस्तावेजी प्रमाण है। भारत में 1904 में सीहोरा जिला जबलपुर तथा बड़ोदरा में पहली बार सहकारी बैंकों का गठन हुआ था। सहकारी समितियों के गठन में जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र अग्रणी रहा है। यहाँ विद्यमान वन संपदा, पशुधन का सहकार के सिद्धांतों पर उपयोग कर स्वावलंबन की दिशा में निरंतर कार्य जारी है। इन कोशिशों ने, संगठन में ही शक्ति है के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए आत्म-विश्वासी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसदीय क्षेत्र में कृषि साख संस्थाएँ एवं सहकारी बैंक, किसान भाइयों की सेवा में सदैव तत्पर रही है। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन के क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र ने सफलता हासिल की है। संसदीय क्षेत्र में सांचौर, जालोर एवं सिरोही जिले की 280 से ज्यादा प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां हैं, यह प्रमुख रूप

से अल्पावधि कृषि ऋण वितरण, कृषि आदान सामग्री प्रदाय, कृषि उत्पादों के उपार्जन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगी हुई है। संसदीय क्षेत्र में करीब-करीब प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों द्वारा भी लघु संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ श्वेत क्रांति की प्रतीक हैं। उस तरह प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां एवं वृहत कृषि बहुउददेशीय सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ रहीं हैं।

केंद्र सरकार ने बढ़ाया पैक्स का दायरा

केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से अब प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां, पैक्स कंप्यूटीकरण योजना के तहत हाइटेक तकनीक से जुड़ने जा रही हैं, केंद्र सरकार की ओर से प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का दायरा बढ़ा कर पैक्स की आमदनी में वृद्धि कर, ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक पहल की गई हैं, पेट्रोल पंप से लेकर एलपीजी गैस एजेंसी और सीएससी केंद्र का संचालन करने का अवसर पैक्स को प्राप्त हुआ है।

सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएं जा रहे कृषि यंत्र

पिछले वर्षों के दौरान नवीन गोदाम निर्माण होने से समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज बिक्री हो रही हैं, तथा किसानों को ऋण वितरण गोदाम कार्यालय भवन पर सुगमता से संभव हो सका हैं, गोदाम निर्माण होने से भविष्य में किसानों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। इसी क्रम में सहकारिता विभाग द्वारा गोदाम विहिन सहकारी समितियों में 100-100 मैट्रिक टन के गोदाम का निर्माण कराया गया हैं, इसी तरह कृषि कार्य में समय की बचत तथा खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से लघु एवं सीमान्त कृषकों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेन्टर से किसान को कृषि उपकरण उचित दर किराये पर मिल रहे है।

इनका कहना हैं

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का सहकारिता पर फोकस हैं, जिससे सहकारिता आंदोलन की सबसे छोटी एवं मजबूत इकाई पैक्स को अनेक प्रकार के व्यवसाय विविधिकरण के अवसर प्राप्त हो रहें हैं, विभागीय योजनाओं को जालोर-सिरोही संसदीय क्षेत्र की कार्यशैली प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां एवं वृहत कृषि बहुउद्देशी सहकारी समितियां द्वारा क्रियान्विति कर आमजन को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा हैं,

हनुमानसिंह राजावत
-जिला अध्यक्ष, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई जालोर

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मनादर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड मनादर

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

श्री वीराराम प्रजापत
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक

हमारी सेवाएं : ■ अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरण ■ कृषि जिंस भंडारण ■ समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद ■ कृषि यंत्रीकरण ■ कृषि आदान ■ पीडीएस

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

अधिकारी-कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों की खुली राह

अनुमोदन

भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (राजपत्रित) सेवा नियम, 2024 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2024 का किया अनुमोदन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है, श्री शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (राजपत्रित) सेवा नियम, 2024 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2024 का अनुमोदन किया है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाएं (सामान्य पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता आएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के सशक्त एवं स्वतंत्र होने से पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठित होने के साथ ही पिछले 10 वर्षों में बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बनाये गए, जिससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं वेतन भ ों के निर्धारण आदि के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे थे।

कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से वाहन चालकों की हो सकेगी भर्ती

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में वाहन चालक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आठवीं से अपग्रेड करते हुए सैकेण्डरी या समकक्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है। श्री शर्मा के इस निर्णय से भविष्य में वाहन चालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा एवं ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जा सकेगा। इससे सुगम एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुशल वाहन चालकों का चयन किया जा सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
नारणावास ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
सुरेश कुमार अध्यक्ष
मफतलाल जीनगर व्यवस्थापक
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का बालोतरा दौरा 'नाकोड़ा तीर्थ का दर्शन कर किया वृक्षारोपण'

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान बालोतरा पहुंचे। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने नाकोड़ा तीर्थ स्थल का दर्शन कर वृक्षारोपण किया। सहकारिता मंत्री श्री दक ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मानसून सत्र में विभिन्न सहकारी संस्थाओं में अधिकाधिक पौधे लगाये जाए और प्रकृति संरक्षण में सहकारी संस्थाएं मह त्वपूर्ण भूमिका निभाए। श्री दक ने बाड़मेर व बालोतरा जिले में दो हजार से अधिक और जोधपुर जोन में दस हजार से अधिक पौधे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पौधारोपण पश्चात उचित सार संभाल भी की जाए। इस दौरान सहकारिता विभाग से शुद्धोधन उज्ज्वल अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जोधपुर जोन और अनिल बिश्नोई, प्रबंध निदेशक बाड़मेर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक उपस्थित रहे।

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जसोल धाम पहुंच कर किए देव दर्शन ; सहकारिता मंत्री एक दिवसीय यात्रा के दौरान जसोलधाम पहुंचे। जहां उन्होंने जगत जननी श्री राणीसा भटियाणीसा के दर्शन पूजन किए। सहकारिता मंत्री श्री गौतम दक के जसोल धाम पहुंचने पर श्री राणी भटियाणी मन्दिर संस्थान की ओर से स्वागत किया गया। सहकारिता मंत्री ने जसोलधाम में जसोल माँ के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि माँ के दर्शनों को आने से बड़ा सुकून मिलता है। जब भी इस क्षेत्र में आता हूँ तो माँ के दर्शन किए बिना नहीं जाता। यहां आने के बाद मन को सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार आया तो विधानसभा चुनाव का मौका था और माँ के दर्शन के दौरान ही मुझे प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। माँ के आशीर्वाद से विजय मिली और प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर आमजन की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि धाम का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। रावल किशनसिंह जसोल के मार्गदर्शन में यहां विकास कार्य हुए है, जिसका लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को मिल रहा है। इस दौरान पचपदरा विधायक अरुण चौधरी भी मौजूद रहे।

101259 किसानों के खाते में 17वीं किस्त का हुआ हस्तांतरण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्त र प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में आयोजित किसान सम्मेलन में पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का हस्तान्तरण किया जिसके तहत लगभग 9.25 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को रू.20,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई जिसमें जालोर व सांचौर जिले के 101259 किसानों के खाते में 17वीं किस्त का हस्तांतरण हुआ। दौरान पशुपालन, कृषि व सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को ई-मित्र, आई चैट बोट, ई-केवाईसी तथा डीबीटी द्वारा प्राप्त किस्त के संबंध में जानकारी दी गई।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
गोदन ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गोदन
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
विक्रमसिंह अध्यक्ष
मांगीलाल चौधरी व्यवस्थापक
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

कृषि विभाग द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को

26 लाख निःशुल्क बीज मिनीकीटों का वितरण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा की अनुपालना में कृषि विभाग द्वारा प्रमुख खरीफ फसलों की उपज बढ़ाने के लिए खरीफ-2024 में कृषकों को ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ व मक्का की उन्नत किस्मों के बीज मिनीकिटों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कृषि आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि प्रदेश के 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख को बाजरा, 4 लाख को मूंग और एक-एक लाख कृषकों को ज्वार व मोठ बीज के मिनीकिट वितरित किये जा रहे है। बीज मिनीकिट के बैगो पर निःशुल्क टैग अंकित है। उन्होंने बताया कि बाजरा मिनीकिट 1.5 किग्रा का,ज्वार, मोठ व मूंग मिनीकिट 4 किग्रा का और मक्का मिनीकिट 5 किग्रा वजन का है। इनका वितरण अनुसूचित जाति व जनजाति, लघु व सीमान्त और महिला कृषकों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच, एक महिला वार्ड पंच, एक अनुसूचित जाति या जनजाति के वार्ड पंच व कृषि पर्यवेक्षक की कमेटी द्वारा किया जा रहा है। सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद द्वारा समस्त कृषकों को मिनीकिट वितरण कार्यक्रम की जानकारी विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषक गोष्ठियों और किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही है। कृषि आयुक्त ने बताया कि कृषकों को मिनीकिट का वितरण राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। एक पात्र कृषक परिवार को एक बीज मिनीकिट ही वितरित किया जायेगा। कृषकों द्वारा आवेदन करने पर प्राप्त आवेदनों को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर कृषकों का चयन किया जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा रखा जायेगा।

"फर्जी आधार कार्ड बनाने" की जानकारी संज्ञान के आने पर

जांच के लिए कमेटी का गठन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आधार कार्ड बनाने में नियमों की अवहेलना कर फर्जी आधार कार्ड बनाने की जानकारी संज्ञान आने पर जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस मामले की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सिस्टम एनालिस्ट योगेश कुमार ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड बनाने की जांच के संबंध में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जालोर के एसीपी (डीडी) सूर्यप्रकाश, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पं.स. जालोर के प्रोग्रामर दिनेश मे घवाल व जिला कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहायक प्रोग्रामर महेन्द्र कुमार बालोत की नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा उक्त प्रकरण की गहनता से जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
सांकरणा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
उम्मेदसिंह अध्यक्ष
वीराराम देवासी व्यवस्थापक
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

दस जुलाई को पेश होगा राज्य का बजट!

जयपुर . प्रदेश सरकार का बजट दस जुलाई को पेश होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसके संकेत दिए। उन्होंने भाजपा कार्यालय में कहा कि बजट हर वर्ग के हित का होगा। काफी लम्बे समय बाद यह देखने को मिलेगा कि इस बार का बजट केन्द्र सरकार के बजट से पहले ही आ रहा है। अक्सर हर बार केन्द्र सरकार का बजट पहले आता है और राज्य की सरकारें बाद में बजट पेश करती हैं।

कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन के सबन्ध में राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि अब तक राज्य में 513 कृषक उत्पादक संगठन बनाये जा चुके है। इनमें से अब तक लगभग 300 एफ.पी.ओ. को खाद, बीज व उर्वरकों के लाईसेन्स जारी किये जा चुके है। भारत सरकार की मंशा अनुसार 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत इन सभी एफ.पी.ओ. को खाद, बीज व उर्वरक, कीटनाशक, मण्डी, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल कॉमर्स के लिए ऑपन नेटवर्क (ओ.एन.डी.सी.) आदि सभी प्रकार के लाइसेन्स पंजीयन करवाये जाने के अभियान चलाये जा रहे है। उन्होंने कहा कि इन अभियानों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये तथा एफ.पी.ओ. से सम्बन्धित सभी हितधारकों को जागरूक कर पूर्व में प्राप्त आवेदनों का अविलम्ब निस्तारण करने तथा आगामी 15 दिवस में सभी एफ.पी.ओ. द्वारा आवेदन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री गालरिया ने बताया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक लाईसेन्स, पंजीयन कार्य का निस्तारण और अगस्त के प्रथम पखवाडे में अनुमोदित लाईसेंस, पंजीयन पत्र आदि का कैम्प लगाकर वितरण किया जायेगा। उन्होंने कृषक उत्पादक संगठनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि किसी भी एफ.पी.ओ. को कठिनाई होने पर संबधित क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) के अधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे एवं जिला स्तरीय समिति, नाबार्ड व कृषि विपणन बोर्ड इसकी पालना सुनिश्चित करेगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा देश भर में 10 हजार किसान संगठनों का गठन करवाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से राज्य में 513 एफ.पी.ओ. का गठन हुआ है। लघु एवं सीमान्त कृषकों को आदान विक्रय व उत्पाद विक्रय के लिए सामूहिक निर्णय क्षमता विकसित करने, उन्हें व्यापार मंच उपल ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा कृषक उत्पादन संगठनों का गठन कर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बैठक के दौरान आयुक्त उद्यानिकी श्री लक्ष्मण सिंह कुडी, प्रशासक कृषि विपणन बोर्ड श्री जयसिंह, नाबार्ड महाप्रबंधक श्रीमती मंजू खुराना, विभागीय अधिकारी एवं कार्यकारी एजेन्सियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
जागनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बागरा
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

श्री जीतू लुकड़ा सहायक व्यवस्थापक
श्री आदाराम लुकड़ा अध्यक्ष
श्री बगदाराम दहिया मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

विधानसभा के 4 कार्मिक सेवानिवृत्त

जयपुर,। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के 4 कार्मिक सहायक सचिव श्री के.के. सैन, सुश्री मुराद बानो, अतिरिक्त निजी सचिव सुश्री मंजू सुखिजा तथा अनुभाग अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा सेवानिवृत्त हुए। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने सेवानिवृत कार्मिकों का विधानसभा में हुए कार्य म में साफा व माला पहनाकर, शॉल ओढाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया। समारोह में विभिन्न संघों द्वारा भी विदाई दी गई। समारोह में विधानसभा उप सचिव (संस्थापन) श्री संजीव शर्मा, बचत एवं साख सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह सहित विधानसभा के अन्य कार्मिकों सहित सेवानिवृत्त कार्मिकों के परिवारजन मौजूद थे।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
लेटा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लेटा
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
खीमाराम अध्यक्ष
भंवलाल टेलर व्यवस्थापक
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

बीमा कंपनी ने नहीं दिया पिछले साल का क्लेम

बीमा कपनी के कार्मिकों की कार्यशैली ठीक नहीं

फसल बीमा कपनी के कार्मिक नियमित रूप से कार्यालय में नहीं बैठते हैं, जिसके कारण यहां आने वाले किसानों को हमें जवाब देना पड़ता है, जबकि काम बीमा कपनी से संबंधित होता है, इसलिए हमारे पास पूरी जानकारी भी नहीं होती. इसको लेकर मैंने कई बार कपनी के पदाधिकारियों को कहा भी है, लेकिन उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा है. यहां बीमा क्लेम को लेकर दिनभर किसानों का तांता लगा रहता है. इससे हम विभागीय कार्य नहीं कर पाते हैं.

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर ; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ढर्रा सुधरने की बजाए और बिगड़ता जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फरवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को उम्मीद जगी थी कि उन्हें फसल खराबे का वाजिब क्लेम मिलेगा, लेकिन बीमा कम्पनियों की मनमानी और उच्चाधिकारियों की उदासीनता के चलते न तो अधिसूचना के नियमों की पालना हो पाती है और न ही किसानों को वाजिब क्लेम मिल पाता है. गत वर्ष सरकार ने निजी बीमा कम्पनियों की बजाए सरकारी बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाकर नागौर में फसलों का बीमा करवाया, लेकिन इस कम्पनी का ढर्रा निजी से भी खराब है. न तो किसानों को समय पर कोई सूचना दी जाती है और न ही फसल खराबे का उचित क्लेम दिया जा रहा है. जिन किसानों के फसल खराबा हुआ, उन्होंने टोल फ्री नम्बर पर सूचना देकर खराबे का सर्वे भी करवाया, लेकिन उन्हें आज तक क्लेम नहीं दिया गया है. ऐसे में जिलेभर के किसान आए दिन कृषि विभाग व कलक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं. बता दें कि खरीफ 2023 में जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल एक लाख, 66 हजार, 668 किसानों ने 5 लाख 67 हजार 786 बीमा करवाए थे. इसके तहत जिले की 4.16 लाख हैक्टेयर भूमि का बीमा हुआ था और इसके बदले कम्पनी ने प्रीमियम राशि के पेटे 168.20 करोड़ रुपए वसूले. इसमें किसानों की ओर से 37.22 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया, जबकि राज्य सरकार की ओर से 65.49 करोड़ व इतने ही केन्द्र सरकार की ओर से प्रीमियम भरा गया. जिले में खरीफ 2023 में कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं सूखा होने के कारण काफी फसल खराबा हुआ था.इसके बावजूद कम्पनी ने 5 लाख 67 हजार 786 एप्लीकेशन में से मात्र एक लाख, 38 हजार 804 एप्लीकेशन पर 129.18 करोड़ रुपए क्लेम देना तय किया है, जबकि कई क्लेम को विभिन्न प्रकार की आपत्तियां लगाकर खारिज कर दिया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कम्पनी ने क्लेम नहीं देने की नीयत से जिले में करीब 642 क्रॉप कटिंग पर झूठी आपत्ति दर्ज करवाई है. कम्पनी कार्मिकों के अनुसार जिले में अब तक कुल 48,439 किसानों का 122.20 लाख रुपए का भुगतान किया गया है. यानी जो प्रीमियम वसूला गया, उससे भी कम क्लेम दिया जा रहा है. नियमानुसार बीमा कम्पनी को जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय पर किसानों को जानकारी देने के लिए कार्यालय खोलने होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक बाद भी तहसील मुख्यालयों पर कार्यालय नहीं खोले हैं. जिला मुख्यालय का कार्यालय भी कृषि विभाग के कम्प्यूटर कक्ष में खोल रखा है, जिसमें कम्पनी के कार्मिक नियमित रूप से नहीं बैठते, इसके चलते किसान परेशान होते हैं. साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को जवाब देना पड़ता है, जिससे उनका विभागीय काम प्रभावित होता है. खास बात यह है कि बीमा कम्पनी कृषि विभाग को न तो कार्यालय का किराया देती है और न ही बिजली-पानी का बिल.

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है ।
अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम..
ग्राम........................ पोस्ट........................
तहसील........................ जिला........................
फोन........................ पिन कोड........................
राशि (रुपए) .... बैंक का नाम........................

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay
9602473302

सदस्यता हेतु लिखें → मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा,
तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041
Mo. 9602473302, Visit Us:Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर, सोमवार, 1 जुलाई 2024
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

स्टाफ की अति अल्पता और प्रशासनिक कारणों से किए तबादले

सीसीबी में प्रबंधक से लेकर बैंकिंग सहायक के हुए तबादले

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में संचालित केन्द्रीय सहकारी बैंक ने स्टाफ की अति अल्पता और प्रशासनिक कारणों से प्रबंधक से लेकर बैंकिंग सहायक तक के तबादले किए, सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर से जारी की गई तबादला सूची में 3 प्रबंधक और 3 बैंकिंग सहायक के तबादले किए गए हैं. जिसमें विवेक उपाध्याय बैंकिंग सहायक ऋण अनुभाग प्रधान कार्यालय को अपने मौजूदा काम के साथ स्थापना अनुभाग प्रधान कार्यालय के बैंकिंग सहायक का भी अतिरिक्त कामकाज सौंपा गया है. इसी तरह महेन्द्रसिंह को सांयकालीन शाखा में प्रबंधक के साथ-साथ कैडर अनुभाग प्रधान कार्यालय जालोर

का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है. इसके अलावा पुखराज आर्य को मेंगलवा शाखा में शाखा प्रबंधक, अमित गहलोत को मुख्य शाखा जालोर में शाखा प्रबंधक बनाया गया हैं, वही, प्रधान कार्यालय जालोर के बैंकिंग सहायक पारस मीणा को आहोर शाखा का काय. ाशाखा प्रबंधक, सायला शाखा के बैंकिंग सहायक मोहित दवे को बैंकिंग सहायक लेखा एवं वित्त, आयोजन एवं विकास कैडर अनुभाग प्रधान कार्यालय जालोर में बैंकिंग सहायक, तो मोहित दवे के स्थान पर श्रीमति पूनम शर्मा को बैंकिंग सहायक शाखा सायला में लगाया गया है।

जिला बंटवारा नीति सीसीबी तक पहुंची

केन्द्रीय सहकारी बैंक में भी राज्य सरकार की जिला बंटवारा नीति साफ झलकने लगी हैं, सीसीबी की ओर से सांचौर जिले की परिधि में संचालित शाखाओं में तबादलों से परहेज नजर आ रहा हैं, तो छह माह में दूसरी बार जारी तबादला सूची में सांचौर जिला परिधि में संचालित अरणाय, चितलवाना, सांचौर, धुबड़िया, रानीवाड़ा शाखा में सालो से एक ही जगह कार्यरत प्रबंधक एवं बैंकिंग सहायकों का तबादला बैंक प्रबंधन की ओर से नहीं किया जा रहा हैं, जबकि जालोर जिले की परिधि में संचालित शाखाओं में निरतंर प्रबंधक एवं बैंकिंग सहायकों को इधर-से-उधर दौड़ाया जा रहा है, वही, चितलवाना, सांचौर, अरणाय शाखा में वर्षो से एक ही जगह कार्यरत शाखा प्रबंधक और बैंकिंग सहायकों के तबादलों पर सीसीबी बैंक प्रबंधन ने मौन धारण कर लिया है। गौरतलब हैं कि केन्द्रीय सहकारी बैंक की चितलवाना शाखा में बैंकिंग सहायक को स्टाफ की कमी का हवाला देकर कार्य. शाखा प्रबंधक पिछले डेढ़ साल से बनाया हुआ है, जबकि पिछले चार साल से वह बैंकिंग सहायक के पद पर रहते हुए भी चितलवाना शाखा में ही कार्यरत हैं, मानो इसे इत्तफाक कहें या बैंक प्रबंधन की कोई रणनीति, जो इस शाखा प्रबंधक के तबादले को लेकर सुत्रो की सीसीबी में कोई बात सुनने तक को तैयार नहीं हैं,

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
कोदरला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कोदरला
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
श्री शिवराम रावल अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार उपाध्यक्ष
श्री देवेन्द्र कुमार सहायक व्यवस्थापक
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

श्री रुपेश कुमार
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
हमारी सेवाएं : ■ अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरण ■ कृषि जिंस भंडारण ■ समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद ■ कृषि यंत्रीकरण ■ कृषि आदान ■ पीडीएस
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
गरल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गरल
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
वीरमाराम अध्यक्ष
हनुमानाराम चौधरी व्यवस्थापक
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

तबादलों को लेकर होमवर्क पूरा, जल्द जारी होगी सूची

जयपुर. विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, इससे पहले भजनलाल सरकार नौकरशाही में बड़ा फेरबदल कर अधिकारियों को इधर-उधर करने की तैयारी में है। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों को लेकर सरकार में उच्च स्तर पर होमवर्क पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि मुयमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग तबादला सूची जारी कर देगा।

अन्न भंडारण योजना के तहत सहकारी समितियों से चाही सूचना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य में केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि के लिए चलाई जा रही, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में राजस्थान के सहकारिता विभाग ने जोधपुर खंड की 11 सहकारी समितियों का चयन कर, वर्ष 2023-24 में संबंधित सहकारी समितियों द्वारा किए गए कुल ऋण वितरण, अन्य व्यवसाय की कुल राशि का विवरण यथा, खाद बिक्री, बीज बिक्री, कीटनाशक बिक्री, पशु आहार बिक्री, अन्य आदि की सूचना सहित समिति प्रबंधन की कार्यक्षमता, सहकारिता एवं समिति में व्यवसाय रुचि पर टिप्पणी चाही हैं, सहकारिता विभाग के पंजीयक कार्यालय के संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) दिनेश शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की क्रियान्विति के लिए खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में समन्वय व पर्यवेक्षण कमेटी का गठन किया गया है। वही, जोधपुर खंड की 11 सहकारी समितियों में से जोधपुर जिले की केरु, शेरगढ़, बड़ला बासनी, आउ, पूनासर, बाड़मेर की सिणधरी, जैसलमेर की 2 पीटीएम, खेतोलाई, सिरोही की गोल, जालोर की जसवतंपुरा, पाली की घाण्डेराव सहकारी समिति को शामिल किया जाएगा

व्यवस्थापकों पदों को लेकर सवालों के घेरों में ज्यादातर सहकारी समितियां ?

सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो का कहना हैं कि निम्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों को केंद्र सरकार की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में शामिल किया जा रहा हैं, उनमें से ज्यादातर सहकारी समितियां व्यवस्थापक पदों को लेकर सवालों के घेरों में हैं, जोधपुर जिले की शेरगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक का पद 5 जुलाई 2008 से रिक्त हैं, तो केरु, आउ, पूनासर ग्राम सेवा सहकारी समिति में अस्थाई सहायको को व्यवस्थापक पद पर नियुक्ति दे रखी हैं, इसी तरह बाड़मेर जिले की सिणधरी में भी व्यवस्थापक का पद रिक्त हैं, वही, सिरोही जिले की नव गठित गोल सहकारी समिति को शामिल करने की कयावद हैं, जबकि इस सहकारी समिति में भी व्यवस्थापक पद की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध आनन-फानन में की गई है। हालांकि सुत्रो का कहना हैं कि इन समितियों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना को लागू करने से पहले रिक्त पदों पर चयनित व्यवस्थापक का पदस्थापन किया जाना चाहिए, ताकि इस योजना की क्रियान्विति में किसी प्रकार कोताही नहीं हो पाए ।

जिला कलक्टर ने किया सहकारी समिति का औचक निरीक्षण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बालोतरा,। जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने आसोतरा ग्राम सेवा सहकारी समिति का गहन निरीक्षण

किया । जिला कलक्टर ने सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली, समिति में संधारित रिकोर्ड, समितियों में मिनी बैंकों की स्थिति, समिति के गोदाम, खाद बीज का स्टोक, ऋण वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा की स्थिति आदि का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने आसोतरा सहकारी समिति के निरीक्षण के दौरान ऋण वितरण व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्य सामग्री के भण्डारण व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलक्टर ने ग्राम सेवा सहकारी समिति को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचे।

सरथला जीएसएस को मिला ट्रैक्टर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

भीलवाड़ा । जिले की मांडलगढ़ तहसील के अंतर्गत संचालित सरथला ग्राम सेवा सहकारी समिति में कस्टम हायरिंग

केंद्र की स्थापना की गई हैं, ऐसे में किसानों को हकाई, उराई और खेती के दूसरे कामों में आ रही परेशानियों से निजात मिलेगी। समिति अध्यक्ष राधेश्याम कंजर ने बताया कि सरथला जीएसएस में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना होने से समिति से जुड़े ऋणी किसानों को हकाई एवं उराई के लिए कृषि यंत्र रियायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे, जिसके लिए किसानों को व्यवस्थापक से संपर्क कर बुकिंग करवानी होगी, साथ ही, दवाइयां के छिड़काव के लिए सहकारी समिति को स्प्रे मशीन सब्सिडी पर किसानों को मुहैया करवाई जाएगी, श्री कंजर का कहना हैं कि किसानों को अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जल्द ही ड्रोन की स्वीकृति दिलाने का प्रयास करुंगा ।

केंद्र सरकार की योजना में धीमी गति के चलते थमाया कारण बताओ नोटिस

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । *प्रदेशभर में केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को डिजीटलीकरण करने का कार्य किया जा रहा हैं, वही, सीसीबी की कुछ शाखाओं के अधीन संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा कछुए की चाल से कार्य किया जा रहा हैं, जिसके चलते राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक धनसिंह देवल ने केंद्र स्तर की अति महत्वपूर्ण योजना में धीमी गति को लेकर 27 केन्द्रीय सहकारी बैंक के 90 से ज्यादा शाखा प्रबंधकों को कारण बताओ* **केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में सबसे बड़ा बाधक FIG पोर्टल बनकर रह गया है, वही, फसली ऋण वितरण एवं वसूली के दौरान हरसमय सर्वर डाउन की समस्या से जुझ रहे इस FIG पोर्टल की समीक्षा करवाने की पहल शीर्ष बैंक प्रबंध निदेशक को करनी चाहिए,** *नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा हैं, हालांकि नोटिस जारी होने के पश्चात कई शाखा प्रबंधकों ने नियमों का हवाला देकर इतिश्री करने की कार्यवाही शुरु कर दी हैं, जबकि सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का कहना हैं कि पिछले सरकार में पैक्स-लैम्पस के फसली ऋण वितरण एवं वसूली कार्य पर केंद्रीय सहकारी बैंकों का एकाधिकार जमाने को लेकर शुरु किए गए फसली सहकारी ऋण पोर्टल की बदौलत आज केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में सबसे बड़ा बाधक FIG पोर्टल बनकर रह गया है, वही, फसली ऋण वितरण एवं वसूली के दौरान हरसमय सर्वर डाउन की समस्या से जुझ रहे इस FIG पोर्टल की समीक्षा करवाने की पहल अपेक्स बैंक प्रबंध निदेशक को करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण स्तर पर सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का समयबद्ध लाभ आमजन को मिलता रहें,*

रायपुर आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रायपुर आदर्श
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
श्री नरपतसिंह अध्यक्ष
राजुसिंह - सहा. व्यवस्थापक
पुष्पेंद्रसिंह ईन्दा सहा. व्यवस्थापक

श्री थानसिंह ईन्दा
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
हमारी सेवाएं : ■ अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरण ■ कृषि जिंस भंडारण ■ समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद ■ कृषि यंत्रीकरण ■ कृषि आदान ■ पीडीएस
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक
विज्ञापन एवं समाचारों के लिए संपर्क करें
Website ; Www.Marwadkamitra.in Mo. 9602473302, 7976323829 Mail ID - marwadkamitra@gmail.com

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
नितौड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नितौड़ा
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
श्री प्रतापराम पुरोहित अध्यक्ष
श्री भेराराम उपाध्यक्ष

श्री दुर्गेश कुमार
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
हमारी सेवाएं : ■ अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरण ■ कृषि जिंस भंडारण ■ समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद ■ कृषि यंत्रीकरण ■ कृषि आदान ■ पीडीएस
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

मानसून : किसानों ने फिर से किया खेत का रुख

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर ; प्रदेश में मानसून की झमाझम बारिश के साथ ही खरीफ की बुवाई में तेजी आई है और किसान परिवार सहित खेत में जुट गया है. इस बार प्री मानसून की बारिश कमजोर रहने के कारण किसान ज्यादा मात्रा में देसी बाजार, ज्वार, मूंग, मोठ और तिल नहीं बो सके हैं. जहां प्री मानसून की बारिश नहीं हुई वहां किसानों ने जमीन में पलाव कर नमी पैदा कर चुका है और अब बुवाई की जा रही है. किसानों की माने तो 15 जुलाई तक बुवाई का काम पूरा हो जाएगा. हर साल प्री मानसून की झमाझम बारिश के साथ प्रदेश के लाखों किसान खरीफ की बुवाई में जुट जाते हैं और मानसून की दूसरी बारिश में ही बीज अंकुरित हो जाता है. लेकिन इस बार प्री मानसून कमजोर रहा और किसान तय समय पर बुवाई नहीं कर सका. अब मानसून के साथ ही बुवाई के काम में तेजी आई है. खरीफ की अनाज फसलों में बाजरे की बुवाई का लक्ष्य 43 लाख 80 हजार हैक्टेयर रखा गया है. जबकि दलहन में मूंग 25 लाख हैक्टेयर में बोया जा सकता है. उधर, तिलहन में मूंगफली की बुवाई का लक्ष्य 11 लाख 50 हजार हैक्टेयर रखा गया है. मानसून लंबा चला तो किसानों को खरीफ में ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है. ऐसे में प्रदेश में कृषि विभाग के तय लक्ष्यों से ज्यादा बुवाई हो सकती है.

एकल पट्टा प्रकरण में जांच के लिए समिति

जयपुर. पूर्व नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े एकल पट्टा प्रकरण की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश आर.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इसमें गृह विभाग के एसीएस एवं प्रमुख नगरीय विकास सचिव सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूर्व न्यायाधीश राठौड़ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। एकल पट्टा प्रकरण में जांच के लिए पूर्ववर्ती सरकार के समय एकल पट्टा प्रकरण को न्यायालय से वापस लेने के लिए समिति बनाई थी,

बैंक एटीएम, सहकारी उपभोक्ता संघ, सरस डेयरी का उद्घाटन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने यहां विधायक आवास परिसर में बैंक एटीएम ई-कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ, सरस डेयरी और चिकित्सालय का उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत, सहकारिता राज्यमंत्री श्री गोतम कुमार, गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग की मौजूदगी में किया। विधायक आवास परिसर में सुविधाओं का निरंतर विस्तार-विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि विधायक आवास परिसर में लगभग 125 विधायकगण और उनके परिजन निवास कर रहे है। परिसर में यहां के निवासियों की आवश यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। एसबीआई बैंक एटीएम का ई-कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ का विविध वस्तु भण्डार, सरस डेयरी का पार्लर और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिये शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का शुभारम्भ किया गया है। भविष्य की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाओं का भी समयानुसार विस्तार किया जायेंगा। चिकित्सा सुविधाओं का होगा विस्तार- श्री देवनानी ने कहा कि चिकित्सालय में वर्तमान में ऐलोपेथी और होम्योपेथी चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। भविष्य में जरूरत के अनुरूप आयुर्वेद चिकित्सकों की भी यहाँ सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। चिकित्सालय का समय भी आवश्यकतानुसार बढाया जायेगा। परिसर में एक समिति का गठन किया गया है, जो यहां निवास कर रहे लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि परिसर की सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किये गये है। यहां रहने वाले विधायकगण, उनके परिजन और उनके अतिथिगण की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं।

सबको साथ लेकर चलेंगे- श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सभी को साथ लेकर चलने के बेहतर प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के आरम्भ होने से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात की जायेंगी। आगामी 2 जुलाई को प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक का मकसद है कि सदन नियमों के अनुसार शांतिपूर्ण चलें। सभी विधायकगण आमजन की समस्याओं को उठायें। उन्होंने कहा कि सदन में उठाई जाने वाली समस्याओं के निस्तारण के पूरे प्रयास किये जायेंगे। श्री देवनानी ने आशा व्यक्त की है कि प्रथम सत्र की भांति द्वितीय सत्र में भी सभी दलों का पूरा सहयोग मिलेगा।

इस मौके पर विधायकगण, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा, विशिष्ट सहायक श्री के.के. शर्मा सहित एसबीआई बैंक एटीएम ई-कॉर्नर के शुभारम्भ के मौके पर मुख्य महाप्रबंधक श्री संदीप भट्नागर, महाप्रबंधक श्री ऋतु गौड, उप महाप्रबंधक श्री संजीव उपाध्याय, क्षेत्रिय प्रबंधक श्री एमजी व्यास और मुख्य प्रबंधक श्री संजय शर्मा, सरस डेयरी की प्रबंध संचालक श्रीमती सुषमा अरोडा, उपभोक्ता संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती शिल्पी पाण्डे, विधानसभा, बैंक, डेयरी, सहकारिता, चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।